

पीएम गतशक्तिराष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूर्ण

प्रलिस के लयः

पीएम गतशक्तिराष्ट्रीय मास्टर प्लान, सारवजनकि-नजी भागीदारी (पीपीपी), परवतमाला रोपवे, आकांक्षी बलॉक कार्यक्रम ।

मेन्स के लयः

पीएम गतशक्तियोजना के कारयान्वयन से संबंघति मुददे , भारतीय लॉजसि्टकिस कषेत्र में चुनौतयिँ

स्रोत: पी.आई.बी.

चरचा में क्यौं?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने [पीएम गतशक्तिराष्ट्रीय मास्टर प्लान](#) के तीन वर्ष सफलतापूरवक पूर्ण होने पर इसे भारत के बुनयिादी अवसंरचना के वकिस में एक परविरतनकारी कदम बताया ।

- प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गतशक्ति मल्टीमॉडल कनेक्टविटी और वभिन्नि कषेत्रों में दक्षता को बढ़ावा दे रही है, जसिसे लॉजसि्टकिस, रोजगार सृजन और नवाचार को लाभ मलि रहा है ।

पीएम गतशक्तिराष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है?

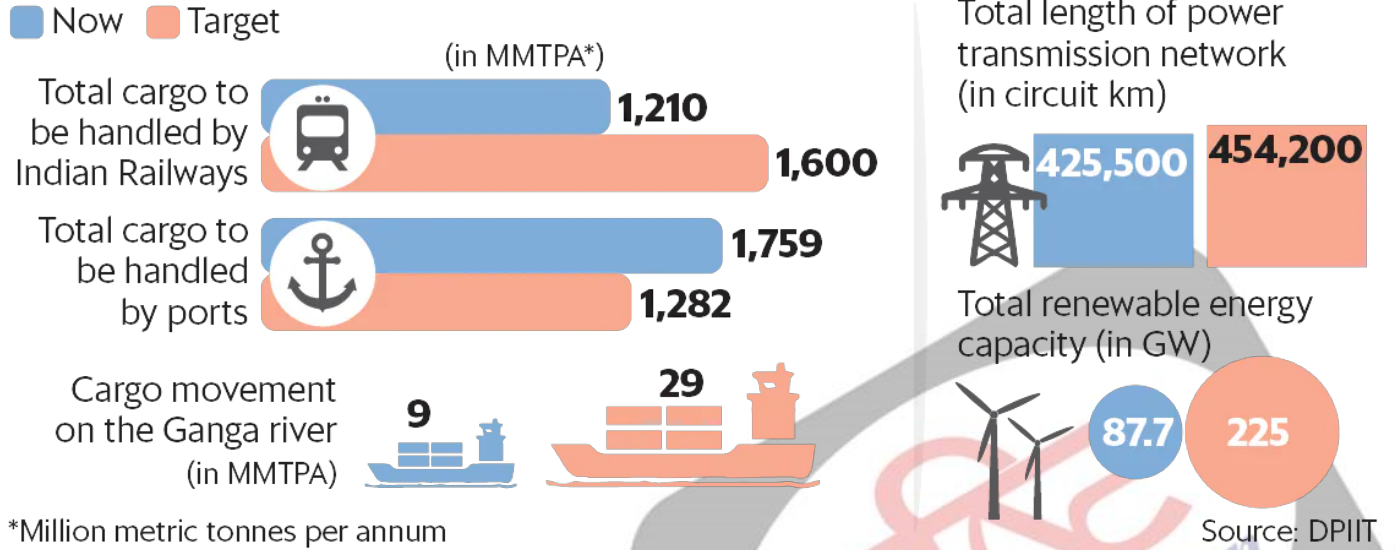
चरचा में क्यौं:

- इसे वर्ष 2021 में भारत सरकार ने लॉजसि्टकिस लागत को कम करने के लयि समनवति और बुनयिादी अवसंरचना परयोजनाओं के नषिपादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गतशक्तियोजना या 'नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टविटी प्लान' लॉन्च कयिा । यह 100 लाख करोड़ रुपए की एक परविरतनकारी पहल है जसिका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में भारत के बुनयिादी अवसंरचना में क्रांतिकारी बदलाव लाना है ।
- इसे **BISAG-N (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरकिष अनुप्रयोग एवं भूसूचना वजिज्ञान संस्थान)** द्वारा **डजिटिल मास्टर प्लानगि टूल** के रूप में वकिसति कयिा गया है ।
 - इसे गतशील भौगोलकि सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म पर तैयार कयिा गया है , जसिमें सभी मंत्रालयों/वभिगों की वशिषि्ट कार्य योजनाओं के आँकड़ों को एक व्यापक डेटाबेस में शामिल कयिा गया है ।
- इस योजना का उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर कार्य में तेज़ी लाने, लागत को कम करने और रोजगार सृजन पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी वर्षों में बुनयिादी अवसंरचना परयोजनाओं की एकीकृत योजना और कारयान्वयन सुनशिचति करना ।

The master plan

The PM Gati Shakti aims to break inter-ministerial silos in infrastructure development. It will be achieved through integrated planning and coordinated implementation between different government departments.

Key targets by FY25



प्रमुख विशेषताएँ:

- **डिजिटल एकीकरण** : इसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे 16 मंत्रालयों के पर्याप्तों को एकीकृत करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों में निरिबाध बुनियादी अवसंरचना परियोजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- **बहु-क्षेत्रीय सहयोग** : इसमें सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, अंतरदेशीय जलमार्ग, शुष्क बंदरगाह और उड्डान सहित कई प्रमुख कार्यक्रमों से बुनियादी अवसंरचनात्मक पहलों को शामिल किया गया है।
- **आर्थिक क्षेत्र** : आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्युटिकल हब, रक्षा गलियारे और कृषिक्षेत्र जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग**: BiSAG-N द्वारा विकसित उन्नत स्थानिक नियोजन उपकरण और इसरो सैटेलाइट मानचित्रण, नियोजन और प्रबंधन के लिये डेटा-संचालित अंतरदृष्टि प्रदान करते हैं।



पीएम गतिशक्ति को संचालित करने वाले प्रमुख आयाम:

- राष्ट्रीय मास्टर प्लान सात प्राथमिक आयामों के इर्द-गिर्द घूमता है जो आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं:

- इन प्रमुख आयामों को ऊर्जा संचरण, आईटी संचार, थोक जल संग्रहण और सीवरेज, और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना जैसे पूरक क्षेत्रों द्वारा भी समर्थन मिलता है।
- इन आयामों को एक साथ मलिकर काम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिससे पूरे देश में रिबाध लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके।

पीएम गतशक्ति के 6 स्तंभ:

- **व्यापकता** : यह योजना एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से सभी मंत्रालयों में वदियमान और नयोजति पहलों को एकीकृत करती है, जिससे महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की दृश्यता बनी रहती है और कुशल नयोजन संभव हो पाता है।
- **प्राथमिकता निर्धारण** : मंत्रालय अंतर-क्षेत्रीय संपर्क का लाभ उठाकर परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्राथमिकता दे सकते हैं, तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इष्टतम आवंटन किया जाए।
- **अनुकूलन** : योजना बुनियादी अवसंरचना में प्रमुख अंतराल की पहचान करती है, परिवहन के लिये सबसे कुशल मार्गों का चयन करने लागत कम करने और देरी को न्यूनतम करने में मदद करती है।
- **समन्वयन** : मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएँ संरेखित हों और सामंजस्य के साथ काम करें, जिससे अलगाव और असमन्वय प्रयासों के कारण होने वाली देरी से बचा जा सके।
- **वश्लेषणात्मक क्षमताएँ** : GIS-आधारित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 200 से अधिक डेटा परतों के साथ, पीएम गतशक्ति बेहतर नरिणय लेने और बुनियादी अवसंरचना की दृश्यता के लिये व्यापक स्थानिक नयोजन उपकरण प्रदान करती है।
- **गतशील नगरानी** : उपग्रह चित्रों के माध्यम से वास्तविक समय पर परियोजना की नगरानी सुनिश्चित करती है कि मंत्रालय प्रगतपर नज़र रख सकें और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये आवश्यक समायोजन कर सकें।

पीएम गतशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **ज़िला-स्तरीय वसितार**: पीएम गतशक्ति ने अपने प्लेटफॉर्म को 27 आकांक्षी जिलों तक वसितारित किया है, आने वाले महीनों में 750 जिलों तक पहुँचने की योजना है।
- **तकनीकी एकीकरण**: भू-स्थानिक उपकरणों और गतशील डेटा परतों के उपयोग से वास्तविक समय की बुनियादी अवसंरचना नयोजन और नरिणय लेने में काफी सुधार हुआ है।
- **वैश्विक प्रदर्शन**: गतशक्ति आयाम को मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 30 देशों में प्रदर्शित किया गया है, और हाल ही में इसे हॉनगकॉन्ग में UNESCAP सम्मेलन और एशिया प्रशांत व्यापार मंच में प्रदर्शित किया गया था।
- **सामाजिक क्षेत्र एकीकरण**: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे मंत्रालयों ने MNP का उपयोग करके नए स्वास्थ्य देखभाल सुवधियों के लिये इंटरनेट-शो क्षेत्रों की पहचान की है और साइटों का मानचित्रण किया है।
 - उत्तर प्रदेश ने नए अस्पतालों और गेहूँ खरीद केंद्रों के लिये स्थल का चयन करने के लिये इस मंच का उपयोग किया है।
- **ग्रामीण और शहरी प्रभाव**: गुजरात के दाहोद ज़िले ने कम लागत वाली ड्रिप सिंचाई प्रणाली की योजना बनाने के लिये उपग्रह मानचित्रण का उपयोग किया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने बचिम बांध के आसपास पर्यटन क्षमता वकिसति करने के लिये डेटा वज़िअलाइज़ेशन का लाभ उठाया है।
 - कानपुर, बेंगलुरु और श्रीनगर जैसे शहरों में प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिये शहरलॉजिस्टिक्स योजनाएँ वकिसति की गई हैं।
- **रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण**: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय औद्योगिक क्लस्टरों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निकट प्रशिक्षण संस्थान स्थापति करने के लिये स्थानों की पहचान करने हेतु गतशक्ति दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है।

पीएम गतशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की चुनौतियाँ क्या हैं?

- **डेटा एकीकरण और सटीकता**: कई मंत्रालयों से वास्तविक समय के डेटा को संयोजित करना कठिन है क्योंकि कुछ डेटा पुराने या अधूरे हैं, जिससे योजना कम प्रभावी हो जाती है।
 - उदाहरण के लिये, 13 राज्यों में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो चुका है, जबकि शेष राज्य इस मामले में पीछे हैं, जिससे परियोजना क्रियान्वयन नरितर नहीं हो पा रहा है।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय**: मंत्रालय प्रायः अलग-अलग पदवतसे कार्य करते हैं, जिससे सड़क और रेलवे जैसी प्रमुख परियोजनाओं में वलिंब एवं संसाधनों के लिये संघर्ष होता है।
 - सागरमाला और भारतमाला परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाया गया कि राज्यों और मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय की कमी के कारण प्रगत धीमी हो रही है।
- **वनियामक संबंधी व्यवधान**: परियोजनाओं को विशेषतः पर्यावरणीय एवं भूमि संबंधी मंजूरी के लिये अनुमोदन प्राप्त करने में वलिंब का सामना करना पड़ता है।
 - मार्ग अनुकूलन के लिये उपकरणों के बावजूद, पहाड़ी क्षेत्रों में वदियुत पारेषण परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में समय लगता है, जिससे समग्र प्रगत धीमी हो जाती है।
 - पहाड़ी क्षेत्रों में बजिली एवं सड़क परियोजनाएँ प्रायः पर्यावरण संबंधी चिंताओं, वसिथापन के मुद्दों के साथ-साथ स्थानीय वसिधों के कारण वलिंब का सामना करती हैं, जिससे अनुमोदन और प्रगत धीमी हो जाती है।
- **वतितपोषण एवं संसाधन आवंटन**: बड़ी परियोजनाओं के लिये, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर पर्याप्त वतितपोषण सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

- कई क्षेत्रों में सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP) सीमति है, जिससे वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है, जिससे परियोजना पूर्ण होने में देरी होती है।
- कुशल जनशक्ति का अभाव: उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के विपरीत, सभी राज्यों के पास गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का पूर्ण उपयोग करने के लिये आवश्यक तकनीक या कुशल कर्मचारी नहीं हैं, जो इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं।
- परियोजना नगिरानी एवं जवाबदेही: यद्यपि यह प्लेटफॉर्म वास्तविक समय पर ट्रैकिंग की अनुमति देता है, कति परियोजना अद्यतन हमेशा नयिमति नहीं होते, जिससे पूर्ण होने में देरी होती है।
 - उदाहरण के लिये, कई जिलों में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं पर उचित तरीके से नज़र नहीं रखी जाती परणामस्वरूप प्रगति धीमी हो जाती है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को कैसे बढ़ाया जा सकता है?

- वास्तविक समय डेटा में सुधार: मंत्रालयों को परियोजना डेटा को सटीक एवं अद्यतन रखने के लिये उपग्रह मानचित्रण के साथ भू-स्थानिक डेटा के अपने उपयोग का वसितार करना चाहिये।
 - सभी राज्यों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में तेज़ी लाने से परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और साथ ही पुरानी जानकारी के कारण होने वाली देरी में कमी भी आएगी।
- अंतर-मंत्रालयी समन्वय को बढ़ाना: मंत्रालयों के बीच संचार एवं समन्वय को बेहतर बनाने के लिये अंतर-मंत्रालयी कार्य बल का गठन करना।
 - गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा कि सभी मंत्रालय वास्तविक समय में एक-दूसरे की गतिविधियों पर नज़र रख सकें, जिससे बड़ी परियोजनाओं के लिये देरी और संसाधन के लिये संघर्ष कम हो सके।
- प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना: गतिशक्ति विश्वविद्यालय का वसितार करना और साथ ही बुनियादी अवसंरचना संबंधी योजनाओं एवं परियोजनाओं के प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना, यह सुनिश्चित करना कि राज्य गतिशक्ति उपकरणों का पूर्ण उपयोग कर सकें।
- वनियामक अनुमोदन को सरल बनाना: पर्यावरणीय एवं भूमि भिंजरी प्रक्रियाओं को तीव्र करने के लिये GIS-आधारित उपकरणों का उपयोग करना।
 - विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये अनुमोदन में तेज़ी लाने से परियोजनाओं की गति धीमी करने वाली नियामक बाधाओं को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।
- नजी नविश को आकर्षित करना: बड़े पैमाने की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) एवं सॉवरेन वेलथ फंड्स का उपयोग करना।
 - इससे सरकार पर वित्तीय भार कम करने, संसाधन आवंटन में सुधार करने के साथ-साथ अधिक नजी एवं अंतरराष्ट्रीय नविशकों को आकर्षित करने में सहायता प्राप्त होगी।
- सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना: सभी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को शामिल करना।
 - पर्यावरण एवं सामाजिक चिंताओं को दूर करने, प्रतिरोध को कम करने के साथ विशेष रूप से हमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये योजना प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करना।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

Q. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. 'राष्ट्रीय नविश और बुनियादी ढाँचा कोष' के संदर्भ में नमिनलखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह नीति आयोग का अंग है।
2. वर्तमान में इसके पास 4,00,000 करोड़ रुपए का कोष है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत में 'पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर' पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? (2020)

- (a) डजिटल सुरक्षा अवसंरचना
- (b) खाद्य सुरक्षा अवसंरचना
- (c) स्वास्थय देखभाल और शक्तिषा अवसंरचना
- (d) दूरसंचार और परविहन अवसंरचना

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. अधकि तीव्र और समावेशी आर्थकि वकिास के लयि बुनयिादी अवसंरचना में नविश आवश्यक है।” भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा कीजयिे। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pm-gatishakti-national-master-plan-completes-3-years>

